



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14390

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 28699 वर्ष 2025

रत्नदीप निषाद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

कुमार आशुतोष श्रीवास्तव, नागेंद्र बहादुर सिंह, श्वेता निषाद, विवेक मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, कुंदन मिश्रा, विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक मिश्रा, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री कुंदन मिश्रा एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया में **मुकदमा अपराध संख्या 218 वर्ष 2025**, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 117(2), 103(1) बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, **राज निषाद** को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 31708 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 14.01.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। चूंकि आवेदक की भूमिका उक्त सह-अभियुक्त के समान है, इसलिए वह भी समानता (parity) के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 28.06.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का इस आधार पर कड़ा विरोध किया है कि साक्षी बॉबी देओल द्वारा उपलब्ध कराए गए वायरल वीडियो में सह-अभियुक्त राज निषाद नहीं पाया गया था, बल्कि आवेदक सहित अन्य अभियुक्तों को नामित पाया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभन खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। समानता के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- रत्नदीप निषाद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10.हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220** और **हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में यथाशीघ्र निस्तारित किया जाए।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 20, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।